

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या- 186/XXVII(9)/2010/मनो0कर-16/2010

देहरादून: दिनांक: 22 जुलाई, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

केबिल टेलीविजन नेटवर्क (Regulation) एक्ट, 1995 के अन्तर्गत कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के उल्लंघन पर देख-रेख करने एवं प्राप्त होने वाली शिकायत/अनियमितता का अनुश्रवण करने हेतु भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अ0शा0 पत्र संख्या-3102/1/2008-बी0सी0-2 वाल्यूम 2, दिनांक 16 नवम्बर, 2009 में प्राप्त निदेशों के अनुपालन में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- |    |                                                                                            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना                                                                    | अध्यक्ष    |
| 2. | महानिदेशक (पुलिस) के प्रतिनिधि                                                             | सदस्य      |
| 3. | सचिव, समाज कल्याण                                                                          | सदस्य      |
| 4. | सचिव, महिला एवं बाल विकास                                                                  | सदस्य      |
| 5. | अशासकीय संस्था, जो महिलाओं के लिये कार्य कर रही हो, के प्रतिनिधि (मुख्य सचिव द्वारा नामित) | सदस्य      |
| 6. | बुद्धिजीवी/समाजशास्त्री/मनोवैज्ञानिक (मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक में से एक नामित)          | सदस्य      |
| 7. | निदेशक, सूचना                                                                              | सदस्य सचिव |

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति में मुख्य सचिव द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा एवं एक बार नामित सदस्य पुनः नामित किये जाने योग्य नहीं होगा।

  
(राधा रतूड़ी)  
सचिव।

संख्या- 186 (1)/XXVII(9)/2010/मनो0कर-16/2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, एवं जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

5- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को (अंग्रेजी के रूपान्तरण सहित) आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 50-50 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।

7- गार्ड फाइल।

(एस0एस0 वल्दिया)

उप सचिव ।